THE INDIAN RAILWAY COMPANIES (REPEAL) BILL, 2001

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): Madam, I beg to move:

"That the Bill to repeal the Indian Railway Companies Act, 1895, be taken into consideration."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI NITISH KUMAR: Madam, I move that the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE RAILWAY COMPANIES (SUBSTITUTION OF PARTIES IN CIVIL PROCEEDINGS) REPEAL BILL, 2001

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): Madam, I beg to move:

"That the Bill to repeal the Railway Companies (Substitution of Parties in Civil Proceedings) Act, 1946, be taken into consideration."

The question was proposed.

उपसभापति : आप सिर्फ यह बता दीजिए कि क्यों आप रिपील करा रहे हैं और यह कहां सब्स्टीट्यूट हो गया है।

श्री नीतीश कुमार : महोदया, यह तो बहुत पहले से पड़ा हुआ है, मुझे खुद आश्चर्य हुआ। जब इंडियन रेलवेज़ ऐक्ट 1989 में फिर से नए सिरे से बना, उसी समय इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए था। कांस्टीट्यूशन में पहले ही यह सब्स्टीट्यूट हो गया है। पहले जब कंपनीज़ को लिया गया था तो "गवर्नर जनरल इन काउंसिल" आए, उसके बाद जब 1935 में ऐक्ट बना तो "डोमीनियन ऑफ इंडिया" उसकी जगह पर आया। उसके बाद जब कांस्टीट्यूशन बना तो "यूनियन ऑफ इंडिया" हर जगह रिप्लेस हो गया। अलग से इसकी कोई जरूरत नहीं थी।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Redundant. आज़ादी के बाद ऐसा बिल लाना शोभा नहीं देता।